मिलों को इनसेंटिव देने पर विचार: थॉमस

[पीटीआई । नई दिल्ली]

संकटग्रस्त चीनी मिलों को इनसेंटिव्स देने पर कैबिनेट अगले हफ्ते विचार कर सकती है। यह बात फूड मिनिस्टर के वी थॉमस ने बुधवार को कही। कृषि मंत्री शरद पवार ने इसी महीने कहा था कि भारत सरकार गन्ना किसानों के भुगतान में मदद करने के लिए चीनी मिलों को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर का इंटरेस्ट फ्री लोन देने पर विचार कर रही है। पवार ने कहा था कि रॉ शुगर के प्रॉडक्शन को प्रमोट करने के लिए सरकार अतिरिक्त इनसेंटिव देने पर भी विचार कर रही है। मौजूदा सीजन में चीनी मिलों ने गन्ना पेराई में काफी देरी की है। मिलों ने तय शेड्यूल से करीब एक महीने बाद पेराई का काम चालू किया है। इसके चलते इस सीजन में चीनी का उत्पादन पिछले साल की समान अविध की तुलना में 50 पर्सेंट घट गया है। शुगर इंडस्ट्री को मदद के मुद्दे पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स में इसी सप्ताह चर्चा किए जाने की उम्मीद है।

गन्ना किसानों को पेमेंट के लिए चीनी मिलों को 7 हजार 200 करोड़ रुपये के लोन पर 12 पर्सेंट की इंटरेस्ट सब्सिडी और आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत लोन रिस्ट्रक्चरिंग जैसी कुछ बातें इस इंडस्ट्री के लिए प्रस्तावित रिलीफ पैकेज का हिस्सा हैं। कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि यह प्रस्ताव दो चरणों में जाएगा। एक इसी हफ्ते और दूसरा अगले हफ्ते। उन्होंने डिटेल्स देने से इनकार कर दिया।

Economic Times
13/12/13